फसल खराब होने पर छोटे किसानों को पूरी मदद: पवार

[पीटीआई *नई दिल्ली*]

बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जिन छोटे और सीमांत किसानों की आधी या ज्यादा फसल खराब हो गई है, उनको पूरी जोत के हिसाब से मदद दी गई है। सरकार ने लोकसभा को इस बात की जानकारी मंगलवार को दी।

एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार ने लोकसभा को बताया, 'सरकार ने चक्रवात, बादल फटने, सूखे, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, फसलों पर कीड़ों के हमले, सुनामी और शीतलहर जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने पर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड (एनडीआरएफ) और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड (एसडीआरएफ) से राहत के लिए गाइडलाइंस तैयार किए हैं।' उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि जिन छोटे और सीमांत किसानों की 50 फीसदी या ज्यादा फसल खराब हुई है, उन्हें पूरी फसल के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दूसरे किसानों को एक हेक्टेयर की फसल के हिसाब से सहायता दी जाती है, चाहे उनके पास खेती की कितनी भी जमीन हो।

पवार ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा, 'जब भी कोई आपदा आती है, केंद्र सरकार राहत मुहैया कराती है। मुआवजे और राहत में अंतर है। ऐसे मामलों में हम राहत देते हैं। फाइनेंस कमीशन सिफारिश करता है और आमतौर पर सरकार इन्हें मंजूर भी कर लेती है।' उन्होंने बताया कि सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात ने सूखे का हवाला देते हुए राहत की मांग की है।

एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बताया कि जब कभी राज्य प्राकृतिक आपदा के चलते फसल का नुकसान होने पर राहत मांगते हैं तो उनकी मिनिस्ट्री नुकसान का हिसाब लगाने के लिए एक टीम बनाती है उसे प्रभावित इलाकों में जाकर रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है। इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी उस रिपोर्ट का अध्ययन करता है और फिर आगे की कार्रवाई का फैसला किया जाता है।

झारखंड से बीजेपी सांसद रवींद्र पांडेय ने कहा कि राज्य में पिछले तीन साल से सूखा है, लेकिन इसको लेकर केंद्र की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए। इस पर शरद पवार ने कहा कि राज्य से सहायता के लिए अनुरोध नहीं मिला। मेमो मिलने पर कदम उठाए जाएंगे। जब बीएसपी सांसद गोरखनाथ पांडेय ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहा, तो पवार ने कहा कि फौरी राहत मुहैया कराना राज्य की जिम्मेदारी है।

पवार ने कहा, 'ज्यादा नुकसान होने पर केंद्र सरकार आगे आती है। हम किसानों की मदद को तैयार है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि अगर यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाके को लेकर लिखित मेमो मिलता है तो मैं 48 घंटे के भीतर टीम बना दूंगा।

Economic times

28/8/13